

मूल अधिकार तथा उत्पत्ति

मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च कानून में निहित किया गया हो और विधान-सभिका तथा कार्यपालिका स्वीकार करती हो। इसे संविधान के तृतीय भाग में रखा गया है और भारतीय जनता की अनन्य स्वतंत्रताओं का अधिकार प्रथम (Article 1) माना जाता है। मूल अधिकार वह अधिकार हैं जिसमें भारत के सभी नागरिकों को चाहे वे देश के किसी भी भाग के निवासी हों, किसी भी धर्म, सम्प्रदाय के अनुयायी हों सभी को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है।

मूल अधिकारों में 'मूल' शब्द का यह अर्थ नहीं है कि इन अधिकारों को बरखा नहीं जाता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पटेल जी साहब ने यह निर्णय दिया था कि संसद को मूल अधिकार वाले भाग में संशोधन करने का अधिकार है। और संविधान के 24 वें और 25 वें संशोधन द्वारा संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

4 मूल अधिकारों की विशेषताएँ —

- (i) मूल अधिकार नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हो
- (ii) मूल अधिकारों को सभी सरकारें मान्यता देने तथा अर्थात् कर्तव्य से बाध्य ।
- (iii) मूल अधिकारों की संरक्षण व्यापकता ।
- (iv) सरकार की निरंकुशता पर उद्देश्य ।
- (v) कुछ अधिकार भारत में स्वयं वाक्य सभी व्यक्ति को प्राप्त हो
- (vi) राष्ट्र तथा समाज हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध
- (vii) मूल अधिकार भारत के परिस्थितियों के अनुकूल
- (viii) मूल अधिकारों को भारत के संविधान में स्थान ।

(1) मूल अधिकार नागरिकों को समान रूप से प्राप्त — मूल अधिकार देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है।

Dr. Anshu